50 गुना बढ़ी भारत की सौर ताकत

एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 1.62 लाख मेगावाट पहुंची

नयी दिल्ली, 03 अगस्त भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में करीब 50 गुना बढ़कर 1.62 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है.

इसी तेज विस्तार के चलते भारत ने सालाना सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते सौर ऊर्जा बाजार का स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और ऊर्जा क्षेत्र को पारंपरिक स्रोतों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की भी जरूरत महसूस हो रही है. बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में देश की कुल बिजली खपत 170.70 अरब यूनिट रही, जबकि जुलाई 2025 में यह 153.88 अरब यूनिट थी. इस तरह सालाना आधार पर बिजली खपत में 10.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. मानसून के बावजूद बिजली की मांग में यह उछाल कई राज्यों में बनी उच्च आर्द्रता और उमस से जुड़ा माना जा रहा है. वास्तविक तापमान अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद अधिक नमी के कारण लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हुई, जिसके चलते एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा. इसका सीधा असर बिजली की खपत और मांग पर पड़ा.

> पिछले दस वर्षों में सौर क्षमता में करीब 50 गुना विस्तार इस बात का संकेत है कि देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से निवेश और क्षमता निर्माण किया है. बड़े सौर पार्कों से लेकर रूफटॉप सोलर और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन तक, सौर ऊर्जा का दायरा लगातार बढ़ रहा है. सालाना क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ना भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में देश की बढ़ती हिस्सेदारी और निवेश क्षमता का संकेत मिलता है.

पश्चिम एशिया संकट से 18,150 करोड़ नुकसान

नयी दिल्ली, 03 अगस्त पश्चिम एशिया संकट के कारण सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर 18,150 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ. पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के साथ हुई थी. हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ गयी. इससे तेल विपणन कंपनियों की कच्चे माल की लागत बढ़ गयी. देश की तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को इस कारण पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा. इंडियन ऑयल का नुकसान 2,661 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम का 3,962 करोड़ रुपये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 11,526 करोड़ रुपये रहा.

भारत ने मंजूर किए 10 हजार करोड़

63 प्रस्तावों से आएंगे 10,292 करोड़ रुपये के निवेश

चीन का केवल एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव हुआ मंजूर

नई दिल्ली, 3 अगस्त. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 10,292.67 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी है. इस दौरान कुल 63 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, लेकिन इनमें चीन की हिस्सेदारी बेहद सीमित रही. सरकार ने चीन से आए केवल एक निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसकी कुल राशि मात्र एक करोड़ रुपये है.

वहीं हांगकांग से आए 13 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिनका कुल मूल्य

610.42 करोड़ रुपये रहा. इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियम लागू होने के बाद चीन से भारत में आने वाले निवेश पर अब भी सख्त निगरानी जारी है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच स्वीकृत विदेशी निवेश प्रस्तावों का कुल मूल्य करीब 1.18 अरब डॉलर रहा. इस अवधि में सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा. सिंगापुर के पांच निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनके माध्यम से 3,259.88 करोड़ रुपये का निवेश भारत में आएगा.

> सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक संकट या विशेष परिस्थितियों का लाभ उठाकर कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनियों का कम कीमत पर अधिग्रहण न कर सके. इसी कारण अब ऐसे निवेश प्रस्तावों की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गहन जांच की जाती है सरकार की यह नीति रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. वहीं, निवेशकों के लिए भारत अब भी आकर्षक बाजार बना हुआ है, जिसका प्रमाण वित्त वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव हैं.

पीएफ खातों में 8.25% ब्याज जमा होना शुरू

नयी दिल्ली, 03 अगस्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) खातों में 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार देशभर के करीब 34 करोड़ खातों में 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज राशि हस्तांतरित की जा रही है. ऐसे में यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में ब्याज की राशि जमा हुई है या नहीं, तो इसे घर बैठे कुछ आसान तरीकों से तुरंत जांच सकते हैं. ईपीएफओ ने हाल ही में अपने डाटाबेस को नए डिजिटल मंच सीआईटीईएस पर स्थानांतरित किया है. इसके बाद सदस्यों की पासबुक को अद्यतन करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इसी कारण कुछ खातों में ब्याज की राशि तुरंत दिखाई दे सकती है, जबकि कुछ खातों में पासबुक अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए यदि आपके खाते में ब्याज की प्रविष्टि अभी नहीं दिख रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है.

कच्चा तेल 5% से सस्ता, भारत को बड़ी राहत!

मध्य-पूर्व में तनाव कम होने के संकेत से फिसली कच्चे तेल की कीमत

नयी दिल्ली, 03 अगस्त सप्ताह के पहले कारोबारी दिन वैश्विक कच्चे तेल के बाजार से राहत भरी खबर सामने आई. मध्य-पूर्व में तनाव कम होने के संकेतों के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद बाजार का रुख बदला, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ नए हमलों को रोकने और क्षेत्र में समझौते की दिशा में प्रगति का दावा किया. इसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आईं.

इस गिरावट को भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे आयात बिल कम होने, तेल विपणन कंपनियों पर दबाव घटने और शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की संभावना है.

> सोमवार सुबह डब्ल्यूटीआई (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) कच्चा तेल 5.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ करीब 80.20 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा. वहीं ब्रेंट क्रूड भी 4.79 प्रतिशत टूटकर लगभग 83.70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. हालांकि मौजूदा कीमतें अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से अधिक हैं, लेकिन एक दिन में आई यह बड़ी गिरावट ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए राहत का संकेत मानी जा रही है.

इंडिगो का नये नेतृत्व के साथ तीसरे दशक में प्रवेश

नयी दिल्ली, 03 अगस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के पूर्व महानिदेशक विली वॉल्श ने सोमवार को प्रमुख भारतीय विमान सेवा कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया. श्री वॉल्श ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब इंडिगो चार अगस्त को परिचालन के 20 साल पूरे करके तीसरे दशक में कदम रख रही है. वैश्विक विमानन उद्योग में चार दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्री वॉल्श को कंपनी ने इस साल मार्च में सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की थी. इंडिगो के तत्कालीन सीईओ पीटर एल्बर्स के इस साल नौ मार्च को निजी कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के बाद उनकी नियुक्ति की घोषणा की गयी थी.

3,000 करोड़ जुटाएगी फार्मा कंपनी एनबीयू

नयी दिल्ली, 03 अगस्त मुंबई स्थित फार्मा कंपनी एनक्यूब एथिकल्स ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास प्रारूप रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है.

कंपनी ने सोमवार को बताया कि आईपीओ में एक रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इसके तहत प्रवर्तक मेहुल मधुसूदन शाह तथा निवेशक विक्रेता शेयरधारक फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए, न्यूनतम 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए तथा न्यूनतम 35 प्रतिशत खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा. साल 1995 में स्थापित एनक्यूब एथिकल्स लिमिटेड एक वैश्विक स्पेशियलिटी फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कंपनी है. उसे तकनीकी रूप से जटिल टॉपिकल (त्वचा पर लगाए जाने वाले) और ट्रांसडर्मल (त्वचा के माध्यम से दवा पहुंचाने वाले) डोज विकसित करने और निर्माण में गहरी विशेषज्ञता हासिल है. कंपनी इस साल 31 मार्च तक भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे विनियमित बाजारों सहित कुल 50 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है.

अब बदल सकता है यूपीआई से भुगतान का तरीका

संदिग्ध भुगतान पर ग्राहक से दोबारा मांगी जा सकती है अनुमति

ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन

नयी दिल्ली, 03 अगस्त यदि आप प्रतिदिन एकीकृत भुगतान अंतरफलक (यूपीआई) के माध्यम से धनराशि का लेनदेन करते हैं तो आने वाले समय में भुगतान करने का तरीका बदल सकता है.

बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और देश के प्रमुख बैंक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहे हैं. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संदिग्ध भुगतान की स्थिति में ग्राहक से दोबारा पुष्टि ली जा सकती है. पुष्टि मिलने पर ही राशि तुरंत स्थानांतरित होगी, जबकि जवाब नहीं मिलने पर भुगतान में कुछ समय की देरी हो सकती है.

बैंकों की ओर से सुझाव दिया गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा सभी भुगतान पर लागू न होकर केवल उन्हीं लेनदेन पर लागू हो, जिनमें धोखाधड़ी की आशंका अधिक हो. इसके तहत भुगतान करने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दे सकता है, जिसमें ग्राहक से पूछा जाएगा कि क्या वह वास्तव में यह भुगतान करना चाहता है. यदि ग्राहक 'हाँ' का विकल्प चुनता है तो राशि तुरंत भेज दी जाएगी. यदि 'नहीं' का विकल्प चुना जाता है तो लेनदेन रद्द हो जाएगा. वहीं यदि ग्राहक कोई जवाब नहीं देता है तो राशि कुछ समय बाद लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी. बैंकों का मानना है कि यदि हर भुगतान में अनिवार्य रूप से देरी की गई तो डिजिटल भुगतान की गति प्रभावित होगी.

रेलवे ने ढोया 14.10 करोड़ टन माल

नयी दिल्ली 03 अगस्त भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई महीने में 14.10 करोड़ टन से ज़्यादा माल की ढुलाई की है, जो गत वर्ष के इसी महीने की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक है.

रेलवे ने सोमवार को बताया कि इस बार जुलाई महीने में यात्री परिवहन के क्षेत्र में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा. रेलवे ने इस साल जुलाई महीने में 63.35 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 62.19 करोड़ था. उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों ही क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.

इस बार जुलाई माह के दौरान माल ढुलाई 14.13 करोड़ टन रही जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 12.97 करोड़ टन था. इस तरह सालाना आधार पर जुलाई में माल ढुलाई नौ प्रतिशत अधिक हुई. कहा गया है कि यह शानदार प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों की मांग और माल ढुलाई कार्य की क्षमता बेहतर करने के रेलवे के लगातार प्रयासों का परिणाम है.

शेयर बाजारों में चौतरफा लिवाली

544 अंक की बढ़त पर रहा सेंसेक्स

390 अंक से आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 03 अगस्त अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद में सोमवार को शेयर बाजारों में तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 544 अंक की बढ़त में बंद हुआ.

सेंसेक्स करीब 800 अंक की मजबूती के साथ खुला और अंत में पिछले कारोबारी दिवस की

तुलना में 544.39 अंक (0.70 प्रतिशत) ऊपर 78,639.03 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 390.70 अंक यानी 1.6 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,774.30 अंक पर पहुंच गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सोमवार से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लुढ़क गया जिससे भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है. लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा आज करीब साढ़े चार प्रतिशत उतरकर 84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

वृहत बाजार में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.08 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.29 प्रतिशत मजबूत हुआ. निफ्टी मीडिया को छोड़कर सभी सूचकांक सकारात्मक बंद हुए.

समाचार विशेष

सेवानिवृत्ति कर्मियों के कल्याण के लिए कोल इंडिया ने बढ़ाए मदद के हाथ

नई दिल्ली, 03 अगस्त. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शिकायत निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं.

इन पहलों से 4.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. यह राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने वाले अपने पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी पुनः रेखांकित करता है. एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल के तहत, कोल माइंस पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 8 मार्च 2024 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है, जिससे लगभग 40,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिला है. इस निर्णय से सेवानिवृत्त खनिकों तथा उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय संबल प्राप्त हुआ है. सीआईएल ने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन के सहयोग से सी-केयर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन प्रशासन के डिजिटलीकरण को भी गति दी है. इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति संबंधी दावों के निपटान की औसत अवधि 30 दिनों से घटकर मात्र 10 दिन रह गई है. इसके अतिरिक्त, पेंशन संशोधन तथा संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ऑनलाइन जारी करने हेतु नए डिजिटल मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पेंशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निर्बाध एवं पूर्णतः पेपरलेस बनाया जा सकेगा.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहज एवं परेशानी-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ जारी करने तथा कोल माइंस प्रोविडेंट फंड देयों के निपटान की व्यवस्था की गई है, जबकि ग्रेच्युटी का भुगतान वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है.

दिव्यांग बालिकाओं के लिए झंकार महिला मंडल की सौगात

नागपुर, 03 अगस्त. सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवा भावना के अंतर्भाव से आज डब्ल्यूसीएल झंकार महिला मंडल, नागपुर द्वारा संस्कृतिक भवन, नागपुर में एक सेवा गतिविधि का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम के दौरान झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा रीना पांडे द्वारा दो दिव्यांग बालिकाओं नूपुर पिदाबी एवं अक्षरा शंभरकर को उनकी दैनिक आवश्यकताओं एवं आवागमन को सुगम बनाने हेतु क्रमशः एक व्हीलचेयर एवं एक ट्राइसाइकिल भेंट की गई. इस सहयोग से दोनों बालिकाओं की गतिशीलता में उल्लेखनीय सुविधा होगी तथा वे अपने दैनिक

कार्य अधिक आत्मनिर्भरता एवं सहजता से कर सकेंगी. इस अवसर पर झंकार महिला मंडल की उपाध्यक्षा रोज़लीन घोष, डॉ. अर्चना कुमारी, श्रुति परांजपे, डॉ. सोनाली म्हेत्रे, झंकार महिला मंडल की अन्य सदस्याएँ तथा क्षेत्रीय समितियों की अध्यक्षाएं, संगिनी कला मंच एवं मयूरी कला निकेतन सोसायटी के पदाधिकारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. नूपुर पिदाबी एवं अक्षरा शंभरकर तथा उनके परिजनों ने झंकार महिला मंडल की इस मानवीय पहल के लिए अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रीना पांडे एवं झंकार महिला मंडल का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि यह सहयोग उनके दैनिक आवागमन एवं जीवन को अधिक सुगम बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा. नूपुर तैराकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं तथा अक्षरा विद्यालय में शिक्षिका बनना चाहती हैं.

कैबिनेट से मंत्रियों की विदाई का सिलसिला

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से मंत्रियों की विदाई का सिलसिला जारी है. अलग अलग कारणों से मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं. कुछ और मंत्रियों का इस्तीफा होना है, जिसका इंतजार चल रहा है. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थोड़ी अलग परिस्थितियों में हुआ है.

इसकी तुलना यूपीए दो की सरकार में खेल मंत्री रहे सुरेश कलमाड़ी के इस्तीफे से की जा रही है. यूपीए दो की सरकार में कलमाड़ी सबसे पहले मंत्री थे, जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा था. उनके ऊपर कॉमनवेल्थ खेलों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे. उसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया था. मंत्रियों के इस्तीफे और सांसदों की गिरफ्तारी का सिलसिला ऐसा चला कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया और कांग्रेस 2014 का चुनाव बुरी तरह से हारी.

विशेष महाराष्ट्र सरकार में होंगे बड़े फेरबदल, बैठक के बाद मचा हड़कंप

शिंदे गुट के 4 मंत्रियों की छुट्टी तय?

मुंबई. महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जल्द ही बड़े राजनीतिक फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल में भी भारी उलटफेर की चर्चा जोरों पर है. इसी गहमागहमी के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने कोटे के मंत्रियों और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज की करीब दो घंटे तक गहन समीक्षा करने को राजनीतिक गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है.

मंत्रालय में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी विभागों की कार्यप्रगति का विस्तार से जायजा लिया. उन्होंने विकास कार्यों की स्थिति, लंबित परियोजनाओं, पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम में हो रही देरी तथा प्रशासनिक अड़चनों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से जवाब-तलब किया. बैठक में अंतिम चरण में पहुंच चुके विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए. साथ ही आम जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले विभागों पर भी नाराजगी जताई गई. शिंदे ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.

कुछ प्रमुख मंत्रियों के कामकाज पर जताई नाराजगी- राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया गया. चर्चा है कि दादा भुसे, संजय शिरसाट, संजय राठोड और स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर के प्रदर्शन पर शिंदे ने नाराजगी जताई है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

नए चेहरों को मिल सकता है मौका

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र सरकार में भी फेरबदल किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है. हालांकि, महायुति सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई बार दिल्ली का दौरा किया. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद से राज्य के सियासी गलियारों में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को चर्चाएं हो रही है.